भारतीय जनता पार्टी

(केन्द्रीय कार्यालय)
11, अशोक रोड, नई दिल्ली – 110001
फोन नं. : 23005700; फैक्स : 23005787

भाजपा अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह द्वारा 11 मई, 2013 को नई दिल्ली में दिया गया प्रेस वक्तव्य

भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा और उसे छिपाने की कोशिश

यूपीए सरकार बड़े घोटालों के लिए बदनाम हो चुकी है। 550 खरब रुपये से ज्यादा के घोटालों के साथ यह आजाद भारत के इतिहास में अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार साबित हुई है। मौजूदा सरकार के अनियंत्रित भ्रष्टाचार ने हमारे देश में शासन के लिए खतरा पैदा कर दिया है। दुर्भाग्यवश यूपीए की पूरी कोशिश अंत तक उन लोगों को बचाने की रही, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं और वह वह तभी सीमित कार्रवाई करती है, जब उसके पास कोई और विकल्प नहीं बचता।

भ्रष्टाचार और अनुचित कार्य करने के आरोपों का सामना कर रहे दो केन्द्रीय मंत्रियों ने कल रात अपने पद से इस्तीफा दे दिया। प्रधानमंत्री ने अगर इन दागी मंत्रियों को बिना किसी देरी के बर्खास्त किया होता, तो सरकार ने आसानी से बजट सत्र बचा लिया होता। 'खाद्य सुरक्षा ' और 'भूमि अधिग्रहण ' जैसे अनेक महत्वपूर्ण विधेयकों पर बहस होनी थी और इन्हें संसद में पारित किया जाना था, लेकिन अड़ियल यूपीए ने इस अवसर को गंवाना पसंद किया।

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जिस तरीके से रेल मंत्री का बचाव किया उसे लेकर लोग अनेक सवाल उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री, रेल मंत्री को क्यों बचा रहे थे, जबकि उन्हें मालूम था कि उन्हें जाना पड़ेगा? **कांग्रेस पार्टी को रेल मंत्रालय करीब 17 साल के अंतराल के बाद मिला था और सबसे पहली चीज जो रेलवे के बारे में हमने सुनी, वह थी यात्री किराये में भारी बढ़ोतरी और मंत्रालय में प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार।**

पूरी व्यवस्था खतरे में

भाजपा उच्चतम न्यायालय की केन्द्रीय जांच ब्यूरो के बारे में की गई उस टिप्पणी की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहती है, जिसमें उसे सरकार का ''रट्टू तोता'' कहा था। कानून मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय और अन्य अधिकारियों के साथ अपनी रिपोर्ट को साझा करने के लिए सीबीआई को मजबूर किया गया, जबकि उच्चतम न्यायालय ने 'कोलगेट' घोटाले में उससे अदालत को सीधी रिपोर्ट देने को कहा था। श्री अश्विनी कुमार और प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारियों ने स्थिति रिपोर्ट दायर करने के लिए सीबीआई से जबरदस्ती की। यूपीए सरकार द्वारा न्यायिक प्रक्रिया को भ्रष्ट करने का यह बहुत गंभीर

मामला है। इसने पूरी व्यवस्था की ईमानदारी और दायित्व पर अनेक गंभीर सवाल खड़े कर दिये हैं। **हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि न्यायिक प्रक्रिया की गरिमा को बरकरार रखने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा है।**

उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी के बाद, न केवल कानून मंत्री कटघरे में खड़े थे बल्कि प्रधानमंत्री की भी ऐसी स्थिति हो गई जहां उनके लिए अपना बचाव करना मुश्किल था। कानून मंत्री और अन्य अधिकारियों ने ''रिपोर्ट से छेड़छाड़'' की जिसमें उस समय की चर्चा थी जब प्रधानमंत्री स्वयं कोयला मंत्रालय में थे। अगर अश्विनी कुमार को सीबीआई रिपोर्ट को प्रभावित करने के लिए जाना पड़ा तो प्रधानमंत्री कार्यालय को भी क्यों न इस मामले में जवाबदेह बनाया जाए?

चाहे 2जी घोटाला हो या 'कोलगेट' प्रधानमंत्री की भूमिका लंबे समय से संदेह के घेरे में है। 'रिपोर्ट से छेड़छाड़' कर सरकार ने प्रधानमंत्री को अलग करने का विफल प्रयास किया है, लेकिन श्री अश्विनी कुमार के इस्तीफे के बाद पूरी सरकार की पोल खुल गई है।

भाजपा का मानना है कि प्रधानमंत्री से ध्यान बंटाने के लिए श्री अश्विनी कुमार और श्री पवन कुमार बंसल को बलि का बकरा बनाया गया है।

प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारियों की उपस्थिति में कानून मंत्री ने सीबीआई की कोलगेट रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ क्यों की?

क्या यह उस अवधि के कोयला ब्लॉक आवंटन की विस्तृत जानकारी को छिपाने की कोशिश नहीं थी जब प्रधानमंत्री के पास कोयला मंत्रालय था?

2जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के समक्ष श्री ए. राजा को उपस्थित होने की इजाजत क्यों नहीं दी गई?

प्रधानमंत्री जेपीसी के समक्ष उपस्थित होने के लिए तैयार क्यों नहीं हुए, जबकि उन्होंने पीएसी के समक्ष उपस्थित होने की स्वयं पेशकश की थी?

इन सवालों को कोई संतोषजनक जवाब नहीं है।

यह पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रही है। पहले भी स्वर्गीय राजीव गांधी और स्वर्गीय पी.वी. नरसिंह राव के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार को भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार स्थिति एकदम अलग है क्योंकि अब पूरी व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। भारत की जनता का पूरी व्यवस्था पर से तेजी से विश्वास उठ रहा है। एक जिम्मेदार विपक्ष के रुप में, भाजपा महसूस करती है कि भारतीय लोकतंत्र के सभी साझेदारों को दलगत राजनीति से ऊपर उठना चाहिए ताकि हमारी राजनीतिक प्रणाली की विश्वसनीयता को बहाल किया जा सके। **प्रधानमंत्री डा.**

मनमोहन सिंह को यह मेरा सुझाव है कि वे आत्मविश्लेषण करें और फैसला करें कि पूरी राजनैतिक व्यवस्था में लोगों का विश्वास बहाल करने के लिए वे क्या कर सकते हैं।

सरकार नैतिक ताकत पूरी तरह खो चुकी है और संख्या बल पर टिकी हुई है।

यूपीए सरकार की संख्या बल के दो महत्वपूर्ण स्रोत उत्तर प्रदेश के दो दल समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी है।

एसपी और बीएसपी से मेरी अपील है कि अगर वे व्यवस- था के पतन और लोगों के कष्टों से गंभीर रुप से चिंतित है, तो उन्हें यूपीए से तत्काल समर्थन वापस ले लेना चाहिए अन्यथा इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के लिए वे भी समान रुप से जिम्मेदार होंगी।

यूपीए सरकार की विश्वसनीयता इतनी कम हो गई है कि श्री अश्विनी कुमार और श्री पवन बंसल की देरी से रवानगी उसे बहाल नहीं कर सकती।

चूंकि सरकार और उसके पूरे प्रतिष्ठान बहरी हो गई है और संसद में उठी आवाजें उसके कान में नहीं पड़ी हैं, **इसलिए भाजपा ने फैसला किया है कि वह लोगों के पास जाएगी, यूपीए सरकार के ठीक से काम न करने, निष्क्रियता और आकंठ भ्रष्टाचार के विरोध में भाजपा देशभर में धरने देकर और जेल भरो आंदोलन के आहवान के साथ 27 मई से 2 जून, 2013 तक जागरुकता अभियान चलाएगी।**

राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में

यूपीए सरकार के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में है। पड़ोसी देशों के साथ हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर बार–बार घुसपैठ हो रही है। हाल में लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी इलाके में घुसपैठ इसका प्रत्यक्ष और संगीन उदाहरण है। चीनी सैनिक हमारे क्षेत्र में आए और उन्होंने बिना किसी भय के तंबू गाड़ दिये। राजनैतिक इच्छा शक्ति के अभाव के कारण करीब तीन हफ्ते यह मामला अनसुलझा रहा। हांलाकि अब सरकार दावा कर रही है कि घुसपैठ का मामला चीन के साथ सुलझा लिया गया है। लेकिन मीडिया की खबरें हैं कि वह अनकहे समझौते के अंतर्गत हमारे कुछ रक्षा ढांचे (बंकर) ढहाने और चूमर घाटी में गश्त कम करने पर सहमत हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता के मुद्दे पर हम सरकार को पूरा नैतिक समर्थन देने के लिए तैयार है, लेकिन सरकार को स्पष्ट बताना चाहिए कि वास्तव में क्या हुआ है।

विदेश मंत्री श्री सलमान खुर्शीद चीन के सरकारी दौरे पर इस सप्ताह बीजिंग गए। हम उम्मीद कर रहे थे कि अपनी यात्रा के दौरान वे चीनी घुसपैठ के मुद्दे सहित कुछ अन्य मुद्दे भी उठाएंगे, लेकिन हमें यह जानकर निराशा हुई कि कूटनीतिक बातचीत के दौरान उन्होंने इन मुद्दों का जिक्र तक नहीं किया।

लद्दाख में पीएलए की घुसपैठ को एक अलग घटना के रुप में नहीं देखा जा सकता। अगर हम इसे एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखें, तो तस्वीर अलग दिखाई देगी। ऐसा उदाहरण है जब चीन ने पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह का प्रशासनिक नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया, पाक अधिकृत कश्मीर में अपने सैनिक

तैनात किये, अभी भी अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करता है, कई बार जम्मू–कश्मीर के निवासियों को स्टैपल्ड वीजा देता है, ब्रह्मपुत्र के बहाव में बाधा पहुंचाता है। इन सभी चीजों को उसके बड़े उद्देश्यों के रुप में देखा जाता है। भाजपा इन बातों पर यूपीए की नासमझी और भारत के सामरिक हितों की रक्षा के लिए प्रभावकारी कूटनीतिक उपाय नहीं करने पर गंभीर चिंता व्यक्त करती है। चाहे पाकिस्तान का मसला हो या चीन या नेपाल या श्रीलंका या यहां तक कि मालदीव का, यूपीए सरकार के अंतर्गत भारत का समूचा कूटनीतिक प्रभाव धीरे–धीरे कम हो रहा है।

एनडीए के शासनकाल में भारत की विदेश नीति की संरचना न केवल मजबूत और व्यावहारिक थी, बल्कि उसमें दूरदर्शिता और आदर्श थे। अब यूपीए सरकार उस संरचना को पूरी तरह नष्ट कर चुकी है। अगर यूपीए सरकार कमजोर और कूटनीतिक रणनीति के साथ सत्ता में बनी रही, मुझे आशंका है कि यह हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर देगी, जब नैटो सैनिक 2014 में अफगानिस्तान से वापस लाएंगे।

(ओ. पी. कोहली)
मुख्यालय प्रभारी

.